

रजिस्टरेशन नं ०१०/एस ०१४,



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (अनाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला रानियार, 23 फरवरी, 1980/४ फाल्गु ; 1901

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (मतकंता)

श्रद्धिसूचना

शिमला-171002, 23 फरवरी, 1980

संस्था: पर (विज) ए-७(२६१)/७७.—यतः राज्य स कार का अभिभवत है कि उस जांच आयोग को जो कि जांच आयोग अधेनियम, 1952 (1952 का ६०) की धारा ३ के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (अनाधारण) दिनांक 19-१-७७ में प्रकाशित इस विभाग की सम संयक अधिसूचना दिनांक ९-१२-७७ के द्वारा श्री जिद्दा लाल, देवा निवृत्यादमूर्ति, पंजाब उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में, तथा उन मरणोपरान्त राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (अनाधारण) दिनांक १३-६-७९ में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संस्था पर (विज) ए-४(३)/८ दिनांक १३-६-१९७९ के द्वारा श्री बी० सी० मिश्रा, सेवा निवृत्यादमूर्ति, उच्च न्यायालय, देल्ही की प्रयोक्ता में नियुक्त किया गया था, अब जारी रखना अनावश्यक है।

अतः अब ऊर्ध्व आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की शास 7 की उपधारा(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय एतद्वारा उद्द्यत करते हैं नि उक्त जांच आयोग 23-2-1980 से अस्तित्वहीन हो जायेगा।

आज्ञानुसार,  
के ० सी ० पाष्ठेय,  
मुख्य सचिव ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348  
OF THE CONSTITUTION OF INDIA

*Simla-171002, the 23rd February, 1980*

No. Per(Vig)A-7(261)/77.— WHEREAS, the State Government is of the opinion that the continued existence of the Commission of Inquiry appointed under section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), *vide* this department notification No. Per(Vig)A-7(261)/77, dated the 9th December, 1977, published in the *Rajpatra*, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 19th December, 1977, consisting of Shri Jindra Lal, retired Judge of the Punjab High Court and, after the demise of said Shri Jindra Lal, of Shri B. C. Misra, retired Judge of Delhi High Court, appointed *vide* notification No. Per (Vig)A-4(3)/78, dated the 13th June, 1979, published in *Rajpatra*, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 13-6-1979, is unnecessary.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the Governor of Himachal Pradesh, hereby declares that the said Commission of Inquiry shall cease to exist with effect from 23rd day of February, 1980.

By order,  
K. C. PANDEYA,  
*Chief Secretary.*